



प्रधान आयुक्त (अपील्स) का कार्यालय, वस्तु एवं सेवा कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क :
O/O THE PRINCIPAL COMMISSIONER (APPEALS), GST & CENTRAL EXCISE



द्वितीय तल, जी एस टी भवन / 2nd Floor, GST Bhavan
रेस कोर्स रिंग रोड / Race Course Ring Road

राजकोट / Rajkot - 360 001

Tele Fax No. 0281 - 2477952/2441142 Email: cexappealsrajkot@gmail.com

रजिस्टर्ड डाक ए.डी.द्वारा :-

क	अपील / फाइल नम्बर / Appeal / File No.	मूल आदेश नं / O.I.O. No.	दिनांक / Date
	V2/34/GDM/2018-19	07/2018-19	18-05-2018

ख अपील आदेश संख्या (Order-In-Appeal No.):

KCH-EXCUS-000-APP-057-2019

आदेश का दिनांक /

Date of Order: 15.05.2019

जारी करने की तारीख /

Date of issue:

16.05.2019

श्री कुमार संतोष, प्रधान आयुक्त (अपील्स), राजकोट द्वारा पारित /

Passed by Shri Kumar Santosh, Principal Commissioner (Appeals), Rajkot

ग अपर आयुक्त/ मंयुक्त आयुक्त/ उपायुक्त/ सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर/ वस्तु एवं सेवाकर,
राजकोट / जामनगर / गंधीधाम। द्वारा उपरलिखित जारी मूल आदेश से नृजित: /

Arising out of above mentioned OIO issued by Additional/Joint/Deputy/Assistant Commissioner, Central Excise/ST / GST,
Rajkot / Jamnagar / Gandhidham :

घ अपीलकर्ता & प्रतिवादी का नाम एवं पता / Name & Address of the Appellant & Respondent :-

M/s Aashirwad International, B-9, Mundra GIDC,, Opp. Arihant marble,, Barod Road, Mundra (Kutch)- 370421.

इस आदेश (अपील) में व्यापक काई व्यापक निम्नलिखित तरिके में उपयुक्त प्राधिकारों / प्राधिकरणों को नमूद अपील दायर कर सकता है।/
Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal to the appropriate authority in the following way.

(A) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35B के अंतर्गत एवं वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 के अंतर्गत निम्नलिखित जगह की जा सकती है। /

Appeal to Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal under Section 35B of CEA, 1944 / Under Section 86 of the Finance Act, 1994 an appeal lies to:-

(i) वर्गीकरण मूल्यांकन से सम्बन्धित सभी मामलों में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठ, वेस्ट ब्लॉक नं 2, आर.के. पुरम, नई दिल्ली, को की जानी चाहिए। /

The special bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No. 2, R.K. Puram, New Delhi in all matters relating to classification and valuation.

(ii) उपरोक्त परिच्छेद 1(a) में ब्रताए गए अपीलों के अलावा शेष सभी अपीलों में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (निस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, द्वितीय तल, बहुमाली भवन असावा अहमदाबाद- 380016 को की जानी चाहिए। /

To the West regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at, 2nd Floor, Bhaumali Bhawan, Asarwa Ahmedabad-380016 in case of appeals other than as mentioned in para- 1(a) above

(iii) अपीलीय न्यायाधिकरण के नमूद अपील प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) नियमवली, 2001, के नियम 6 के अंतर्गत निर्धारित किए गये प्रपत्र EA-3 को चार प्रतियों में दर्ज किया जाना चाहिए। इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुमाना, रुपए 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्ट्रार के नाम से किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक को उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्थान आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। /

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 / as prescribed under Rule 6 of Central Excise (Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against one which at least should be accompanied by a fee of Rs. 1,000/- Rs.5000/-, Rs.10,000/- where amount of duty demanded/interest/penalty/refund is upto 5 Lac. 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asst. Registrar of branch of any nominated public sector bank of the place where the bench of any nominated public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated. Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs. 500/-

(B) अपीलीय न्यायाधिकरण के नमूद अपील, वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86(1) के अंतर्गत सेवाकर नियमवली, 1994, के नियम 9(1) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-5 में चार प्रतियों में की जा सकती है एवं उनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां सेवाकर की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुमाना, रुपए 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्ट्रार के नाम से किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक को उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्थान आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। /

The appeal under sub section (1) of Section 86 of the Finance Act, 1994, to the Appellate Tribunal Shall be filed in quadruplicate in Form S.T.5 as prescribed under Rule 9(1) of the Service Tax Rules, 1994, and shall be accompanied by a copy of the order appealed against (one of which shall be certified copy) and should be accompanied by a fees of Rs. 1000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied of Rs. 5 Lakhs or less, Rs.5000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than five lakhs but not exceeding Rs. Fifty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs rupees, in the form of crossed bank draft in favour of the Assistant Registrar of the bench of nominated Public Sector Bank of the place where the bench of Tribunal is situated. / Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs.500/-.

- (i) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 की उप-धाराओं (2) एवं (2A) के अंतर्गत दर्ज की गयी अपील, सेवाकर नियमवली, 1994, के नियम 9(2) एवं 9(2A) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-7 में की जा सकती एवं उसके साथ आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा आयुक्त (अपील), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा पारित आदेश की प्रतियाँ संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणीत होनी चाहिए) और आयुक्त द्वारा सहायक आयुक्त अथवा उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सेवाकर, को अपीलीय न्यायाधिकरण को आवेदन दर्ज करने का निर्देश देने वाले आदेश की प्रति भी साथ में संलग्न करनी होगी। / The appeal under sub section (2) and (2A) of the section 86 the Finance Act 1994, shall be filed in Form ST.7 as prescribed under Rule 9 (2) & 9(2A) of the Service Tax Rules, 1994 and shall be accompanied by a copy of order of Commissioner Central Excise or Commissioner, Central Excise (Appeals) (one of which shall be a certified copy) and copy of the order passed by the Commissioner authorizing the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise/ Service Tax to file the appeal before the Appellate Tribunal.
- (ii) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण (सेन्ट्रल) के प्रति अपीलों के मामले में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 35एफ के अंतर्गत, जो की वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 83 के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, इस आदेश के प्रति अपीलीय प्राधिकरण में अपील करते समय उत्पाद शुल्क/सेवा कर मांग के 10 प्रतिशत (10%), जड़ मांग एवं जमाना विवादित है, या जमाना, जब केवल जमाना विवादित है, का भुगतान किया जाए, बशर्ते कि इस धारा के अंतर्गत जमा कि जाने वाले अर्थात् देय राशि दस करोड़ रुपये से अधिक न हो।
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत "नंग किए गए शुल्क" में निम्न शामिल है
- धारा 11 डी के अंतर्गत रकम
 - सेनवेट जमा की ली गई गलत राशि
 - सेनवेट जमा नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत देय रकम
- बशर्ते यह कि इस धारा के प्रावधान वित्तीय (सं० 2) अधिनियम 2014 के आरंभ से पूर्व किमी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विवादाधीन स्थान अर्थात् अपील को लागू नहीं होगा। / For an appeal to be filed before the CESTAT, under Section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under Section 83 of the Finance Act, 1994, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute, provided the amount of pre-deposit payable would be subject to a ceiling of Rs. 10 Crores.
- Under Central Excise and Service Tax, "Duty Demanded" shall include :
- amount determined under Section 11 D;
 - amount of erroneous Cenvat Credit taken;
 - amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules
- provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.
- (C) भारत सरकार कोपुनरीक्षण आवेदन :
Revision application to Government of India:
इस आदेश की पुनरीक्षणयाचिका निम्नलिखित मामलों में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा 35EE के प्रथमपरंतुक के अंतर्गत अवर सचिव, भारत सरकार, पुनरीक्षण आवेदन इकाई, वित्त संचालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जावत दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, को किया जाना चाहिए। / A revision application lies to the Under Secretary, to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35B ibid:
- यदि माल के किमी नुकसान के मामले में, जहां नुकसान किमी माल को किमी कारखाने में भंडार गृह के पारगमन के दौरान या किमी अन्य कारखाने या फिर किमी एक भंडार गृह से दूसरे भंडार गृह पारगमन के दौरान, या किमी भंडार गृह में या भंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किमी कारखाने या किमी भंडार गृह में माल के नुकसान के मामले में। / In case of any loss of goods, where the loss occurs in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse
 - भारत के बाहर किमी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात कर रहे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल पर भरी गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के कूट (रिवेट) के मामले में, जो भारत के बाहर किमी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात की गयी है। / In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of an excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.
 - यदि उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर, नेपाल या भूटान को माल निर्यात किया गया है। / In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.
 - मुनिश्चित उत्पाद के उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो छूटी क्रेडिट इस अधिनियम एवं इसके विभिन्न प्रावधानों के तहत मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो आयुक्त (अपील) के द्वारा वित्त अधिनियम (सं० 2), 1998 की धारा 109 के द्वारा नियत की गई तारीख अथवा ममायाविधि पर या बाद में पारित किए गए हैं। / Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec. 109 of the Finance (No.2) Act, 1998.
 - उपरोक्त आवेदन की दो प्रतियां प्रपत्र संख्या EA-8 में, जो की केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001, के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है, इस आदेश के संश्लेषण के 3 माह के अंतर्गत की जानी चाहिए। उपरोक्त आवेदन के साथ मूल आदेश व अपील आदेश की दो प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए। साथ ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-EE के तहत निर्धारित शुल्क की अदायगी के साथ के तौर पर TR-6 की प्रति संलग्न की जानी चाहिए। / The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the O/O and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.
 - पुनरीक्षण आवेदन के साथ निम्नलिखित निर्धारित शुल्क की अदायगी की जानी चाहिए। जहां संलग्न रकम एक लाख रुपये या उससे कम हो तो रुपये 200/- का भुगतान किया जाए और यदि संलग्न रकम एक लाख रुपये से ज्यादा हो तो रुपये 1000/- का भुगतान किया जाए। The revision application shall be accompanied by a fee of Rs. 200/- where the amount involved in Rupees One Lac or less and Rs. 1000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.
 - यदि इन आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए शुल्क का भुगतान, उपर्युक्त ढंग में किया जाना चाहिए। इस तथ्य के होते हुए भी की लिखा पढ़ी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है। / In case, if the order covers various numbers of order-in Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner, notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellate Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filed to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lakh fee of Rs. 100/- for each.
 - यथासंशोधित न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1975, के अनुसूची-1 के अनुसार मूल आदेश एवं स्थगन आदेश की प्रति पर निर्धारित 6.50 रुपये का न्यायालय शुल्क टिकिट लगा होना चाहिए। / One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjudicating authority shall bear a court fee stamp of Rs.6.50 as prescribed under Schedule-1 in terms of the Court Fee Act, 1975, as amended.
 - सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्य विधि) नियमावली, 1982 में वर्णित एवं अन्य संबन्धित मामलों को सम्मिलित करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। / Attention is also invited to the rules covering these and other related matters contained in the Customs, Excise and Service Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.
 - उच्च अपीलीय प्राधिकारी को अपील दाखिल करने में संबंधित व्यापक, विस्तृत और नवीनतम प्रावधानों के लिए, अपीलार्थी विभागीय वेबसाइट www.cbcc.gov.in को देख सकते हैं। / For the elaborate, detailed and latest provisions relating to filing of appeal to the higher appellate authority, the appellant may refer to the Departmental website www.cbcc.gov.in.

:: ORDER IN APPEAL ::

M/s. Aashirvad International, 8-9, Mundra GIDC, Opp. Arihant Marble, Barod Road, Mundra (Kutch),(hereinafter referred to as "the Appellant") against Order-In-Original No. 07/2018-19/ dated 18.5.2018 (*hereinafter referred to as "the impugned order"*), issued by the Assistant Commissioner, GST, Divisions, Mundra (*hereinafter referred to as "the adjudicating authority"*).

2. The brief facts of the case are that the appellant filed refund claim of Rs.4,93,090/- on 12.3.2018 under Notification No.41/2012-ST dated 29.6.2012 (*hereinafter referred to as "the Notification"*) for service tax paid by them on services utilized by them for export of goods from Dec,2016 to Jan,2017. The lower adjudicating authority vide the impugned order rejected refund on the ground that the claim is beyond the time limit prescribed under Notification. 41/2012-ST dated 29.6.2012.

3. Being aggrieved by the impugned order, the appellant filed the present appeal, on the following grounds:-

(i) The refund was rejected without giving any show cause notice for proposing rejection of refund; that Principle of Natural Justice has not been followed in this case; that they relied upon the Hon'ble CESTAT's decision in the case of M/s. Monarch Catalyst P Ltd reported as 2015(37)STR 1021 (Tri. Mumbai) .

(ii) Filing of refund claim within one year is a procedural one and not a "condition" as held by the lower adjudicating authority; that for procedural lapses, substantive benefit may not be denied; that they relied upon the Hon'ble CESTAT's decision in the case of M/s. Ordinance Factory reported as 2017(358) ELT 1229 (Tri-Mum), M/s. Exide Industries Ltd reported as 2017 (357) ELT 414 (Tri-Chennai); M/s. Skipper Electricals reported as 2017 (355) ELT 591 (Tri-Del) and M/s. Pearl Insulations P Ltd reported as 2016 (344) ELT 1022 (Tri-Bang).

4. Personal hearing was attended by Shri R.C. Prasad, Consultant, who reiterated the grounds of appeal and submitted that time limit of one year is not condition of the notification but only a manner; that substantive benefit of refund should not be rejected merely because claim has been filed late by 2 months; the Hon'ble CESTAT in many cases like M/s. Monarch Catalyst reported as 2015 (37) STR 1021 (Tri-Mumbai) and Ordinance Factory 2017 (358) ELT 1229 (Tri-Mumbai); that the Hon'ble Bombay High Court in the case of M/s. Farheen Texturisers reported as 2015(323) ELT 104 (Bom.) has held that refund/ rebate

claim should not be rejected on technical lapses.

FINDINGS

5. I have carefully gone through the facts of the case, the impugned order, the grounds of appeal memorandum and submissions made during the personal hearing. The issue to be decided in the present case is as to whether refund rejected by the lower adjudicating authority on ground of time bar is correct or not?

6. I find that the lower adjudicating authority has rejected refund on the ground that the claim was filed beyond the stipulated time limit of one year. It is appellant's contention that the principle of natural justice was not followed and refund was rejected without hearing them. I find that the lower adjudicating authority at Para 4 of the impugned order has held as under:-

"4. On scrutiny of the said refund, it is found that the claimant has filed refund claim for the services received for the export of goods for the period Dec,2016 to Jan,2017 vide application dated 11.01.2018 received in this office on 12.03.2018. Thus, the claim filed by the appellant is beyond the time limit as prescribed in Notification No. 41/2012-ST dated 29.6.2012. The claimant has produced letter dated 10.5.2018 waiving SCN & PH and giving his consent to reject the claim. Therefore, this refund claim of Rs.4,93,090/- is required to be rejected."

6.1 I also find that the Appellant has not rebutted the above findings ;that vide their letter dated 10.5.2018, they waived requirement of SCN & PH. Therefore, I am of the view that once Appellant has waived to issue SCN & PH, they cannot cry foul on non-issue of SCN and or not holding PH in the appeal proceedings on their second thought. I, therefore, hold that appeal can't be allowed on the ground of principle of natural justice.

7. The appellant also vehemently contended that substantial benefit cannot be denied on procedural lapse i.e. late filing of rebate claim in this case. I find that clause (3)(g) of Notification 41/2012-St dated 29.6.2012 very specifically stipulates time limit to claim rebate under the scheme which reads as under:-

"(g) the claim for rebate of service tax paid on the specified services used for export of goods shall be filed within one year from the date of export of the said goods.

Explanation. - For the purposes of this clause the date of export shall be the date on which the proper officer of Customs makes an order permitting clearance and loading of the said goods for exportation under section 51 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962);"

(Emphasis supplied)

[Handwritten signature]

7.1 It is trite law that conditions prescribed under the relevant Notification are required to be followed strictly and non-observance of the condition governing Notification cannot be construed as a procedural lapse. It is also settled legal position that Notifications should be construed strictly and to become eligible for a particular scheme or exemption, the conditions of the Notifications must be followed. I find that no discretionary power is vested under the provisions of the Notification for condonation of delay, if rebate claim is filed late. I find that the Hon'ble President of CESTAT in the case of M/s. Life Long India Limited reported as 2016(43) STR 314 (Tri-Del) has held as under:-

"5. In respect of those claims which were found by the impugned order as well as the primary adjudication orders to be beyond the period of limitation, Id. counsel for the appellants contends that since the delay was not considerable, the authorities below should have exercised discretion and condoned the same. This contention does not commend acceptance by the Tribunal. Paragraph 3(g) of the Notification No. 41/2012-S.T. clearly indicates the period of limitation and provides no discretion for condonation of the delay. In the circumstances, it cannot be gainfully contended that the authority had a reservoir of discretion to condone the delay, if satisfied with reasons for the delay for making an application for refund.

6. Insofar as the finding that the services were not used beyond the place of removal, it is clear that the place of removal is not the factory gate as claimed by the appellant but is the port from where the goods were removed for export.

7. On the analyses above, the conclusions in the impugned orders as to the unsustainability of refund claims submitted by the appellant, are impeccable and warrant no appellate interference. There are no merit in the appeals which are therefore dismissed, but in the circumstances without costs."

(Emphasis supplied)

7.2 In view of above, I hold that the rebate claim is hit by limitation and the lower adjudicating authority is correct in rejecting the rebate claim on the ground of limitation.

8. Accordingly, I reject the appeal and uphold the impugned order.

९. अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।

9. The appeal filed by the Appellant is disposed off as above.

(कुमार संतोष)

प्रधान आयुक्त(अपील्स)

पंजीकृत डाक द्वारा

सेवा में

M/s. Aashirvad International, 8-9 Mundra GIDC, Opp. Arihant Marble, Barod Road, Mundra (Kutch) -370421	मेसर्स आशीर्वाद इंटरनेशनल ८-९, मुँदरा जी आई डी सी अरिहंत मार्बल के सामने बरोड रोड, मुँदरा। कच्छ (३७०४२१)
--	---

प्रति,

- १ प्रधान मुख्य आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गुजरात क्षेत्र, अहमदाबाद को जानकारी हेतु।
- २ आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कच्छ आयुक्तालय, गांधीधाम को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
३. सहायक आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर डिवीजन, मुँदरा।
४. गार्ड फाइल